RNI No: UPHIN/2023/86769 www.swarajindianews.com swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

मूल्यः ₹ 02

# स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

कानपुर, गुरुवार, 10 जुलाई, 2025
वर्षः 02, अंकः 186, पृष्ठः 8+4

कैबिनेट के फैसलों को पलट रही अफसरशाही » Pg 12

इनसाइड एडीएम अमित कुमार के खिलाफ सवर्ण समाज में आक्रोश... » Pg 04

# तत्कालीन सीएमओ डॉ हरिदत्त नेमी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश

## कानपुर के तत्कालीन सीएमओ के खिलाफ शासन ने कसा शिकंजा, विभागीय जांच के निर्देश दिए

» मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

**कानपुर।** कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. हरिदत्त नेमी एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। हाईकोर्ट से बहाली के बाद अब प्रदेश सरकार ने उन पर लगे गंभीर आरोपों की जांच के आदेश दे दिए हैं। शासन ने नेमी पर एनआरएचएम गाइडलाइंस की अनदेखी, शासनादेशों के उल्लंघन और लापरवाहीपूर्ण कार्यशैली जैसे आधा दर्जन से ज्यादा आरोप लगाए हैं।

स्वास्थ्य महकमे के उच्च पद पर बैठे डॉ. हरिदत्त नेमी पर शासन ने आरोप लगाया है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। शासन का यह भी कहना है कि अधिनस्थ कर्मचारियों पर उनका नियंत्रण बेहद कमजोर रहा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में अराजकता जैसी स्थिति पैदा हुई।

शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही, प्रशासनिक शिथिलता और कार्यों में अनियमितता जैसे गंभीर बिंदुओं को आधार बनाकर शासन ने सीएमओ के खिलाफअनुशासनात्मक कार्यवाही की

प्रक्रिया शुरू कर दी है। डॉ. नेमी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच अब डायरेक्टर स्तर के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी गई है। उन्हें एक महीने के भीतर जांच पूरी कर शासन को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। साथ ही हरिदत्त नेमी को जांच में पूर्ण सहयोग करने के आदेश दिए गए हैं।

**क्या बहाली सिर्फ तकनीकी थी, या न्याय की चूक?:** हाल ही में कोर्ट के आदेश पर बहाल हुए सीएमओ की कार्यशैली पहले दिन से ही सवालों के घेरे में रही है। सूत्रों की मानें तो स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही एक बड़ा वर्ग उनके कार्य करने के तरीके से असंतुष्ट है और लंबे समय से उनके खिलाफ शिकायतें शासन तक पहुंच रही थीं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोर्ट से मिली बहाली सिर्फ तकनीकी आधार पर थी? अगर शासन के पास इतने गंभीर तथ्य पहले से थे, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और क्या अब शासन की जांच सिर्फ खानापूरी बनकर रह जाएगी या एक बड़ा प्रशासनिक उदाहरण बनेगी?

## विधानसभा में हुए असंबद्ध

### सपा से निकाले गए तीन विधायक

**लखनऊ।** सपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते अपने तीन विधायकों को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। ये तीन विधायक हैं मनोज कुमार पांडेय, राकेश प्रताप सिंह, और अभय सिंह। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5 जुलाई को पत्र जारी कर इस फैसले की जानकारी दी थी। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने भी इन तीनों विधायकों को 9 जुलाई 2025 से असंबद्ध घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि अब ये विधायक विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है।

**क्यों की गई यह कार्रवाई?:** पिछले कुछ महीनों से इन तीनों विधायकों का पार्टी लाइन से अलग चलना, भाजपा के प्रति नरम रुख दिखाना और सपा के कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखना चर्चा में था।

सख्ती

## चेंबर को बनाया 'विवाह स्थल', दो वकीलों पर आपराधिक कार्रवाई के आदेश

# हाईकोर्ट परिसर में जबरन शादी का पर्दाफाश

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था के गढ़ लखनऊ हाईकोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिला की याचिका पर हाईकोर्ट परिसर में जबरन कराई गई शादी का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ। कोर्ट के चेंबर को 'विवाह स्थल' में तब्दील करने, मानसिक प्रताड़ना और अवैध गतिविधियों की पुष्टि होने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए दो

अधिवक्ताओं पर आपराधिक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। महिला की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट परिसर के चेंबर संख्या जीओ-31 में उसकी जबरन शादी कराई गई, और अब उसे

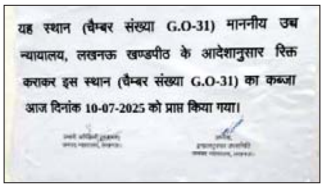

यह स्थान (चैम्बर संख्या G.O-31) माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के आदेशानुसार रिक्त कराकर इस स्थान (चैम्बर संख्या G.O-31) का कब्जा आज दिनांक 10-07-2025 को प्राप्त किया गया।

लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने वजीरगंज पुलिस को जांच के निर्देश दिए।

**फूलों की सजावट, मंडप और बारात जैसी थीम:** जांच के दौरान वजीरगंज पुलिस ने चौंकाने वाले साक्ष्य जुटाए। पुलिस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जीओ-31 को बाकायदा फूलों से सजाया गया था, शादी का मंच तैयार किया गया था और एक 'बारात थीम' की पूरी व्यवस्था की गई थी। न्यायालय ने इसे न्यायिक गरिमा का घोर उल्लंघन बताया। हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश पर चेंबर को तत्काल सील कर दिया गया। पुलिस ने चेंबर को बंद किया और अवैध विवाह केंद्र पर ताला लगा दिया।

## दो वकीलों पर आपराधिक कार्रवाई के आदेश

कोर्ट ने इस प्रकरण में दो अधिवक्ताओं को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि कोर्ट परिसर की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हाईकोर्ट ने साफ संकेत दिए कि कोर्ट परिसर में अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

# कार के नंबर से खुली साजिश, दारोगा की कार सफेद, आरोप में काली बताई

**प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया**

कानपुर। बीते दिनों कानपुर के किदवई नगर चौकी प्रभारी दरोगा प्रवास शर्मा पर लगे अपहरण और वसूली के संगीन आरोपों ने शहर की फिजा को सख्त कर दिया था। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में सच की परतें एक-एक कर खुल रही हैं और वो चौंकाने वाली हैं, दर्दनाक हैं, और खतरनाक इशारा कर रही हैं कि ईमानदारी को अपराधियों ने घेर लिया है।

» सिर्फ नंबर प्लेट नहीं एक ईमानदार दरोगा की पहचान चुराने की साजिश थी!

» वेन्यू कार के नंबर से खुली साजिश की परत दरोगा की गाड़ी सफेद, आरोप में काली

» ना होटल का नाम, ना सीसीटीवी फुटेज फर्जीवाड़े की कहानी अब खुद सवालों में घिर गई

सबसे पहले, प्रार्थना पत्र में दर्ज उस कार का नंबर, जिसे कथित अपराध में इस्तेमाल किया गया बताया गया है दरअसल वही नंबर दरोगा प्रवास शर्मा की निजी सफेद वेन्यू कार का है। लेकिन शिकायत में उसी नंबर को काली रंग की कार से जोड़ा गया है। सवाल यह है क्या किसी ने जानबूझकर दरोगा की कार का नंबर चुराकर एक नकली सीन गढ़ा? या फिर घटना कभी हुई ही नहीं?दूसरा अहम बिंदु शिकायतकर्ता ने दावा किया कि दरोगा ने उसे एक होटल में रात भर बंधक बनाकर पीटा, लेकिन अब तक न उस होटल का नाम सामने आया, न कोई सीसीटीवी फुटेज और न ही पुलिस या प्रशासन के पास ऐसी कोई भौतिक पुष्टि उपलब्ध है जिससे इन दावों की सच्चाई तय हो सके।

तीसरा अहम बिंदु शिकायत में एक विंग शोरूम (साकेत नगर) का भी जिक्र है, जहां कथित रूप से पैसे का आदान-प्रदान हुआ और सीसीटीवी में सबकुछ कैद हुआ बताया गया। लेकिन वह फुटेज भी अब तक नहीं मिला। आखिर ये सबूत क्यों नहीं आ रहे? क्या ये कभी थे ही नहीं?

पुलिस ने मामला अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर लिया है, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब आरोप लगाने वाले युवक ने एक प्रतिष्ठित समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में खुद स्वीकार किया कि उसे कुछ तथाकथित पत्रकारों ने बहकाया और दरोगा प्रवास शर्मा पर झूठा केस दर्ज करवाने को उकसाया। अब सवाल केवल जांच का नहीं रहा यह सवाल न्याय और नीयत दोनों का है।

क्या एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की छवि को बर्बाद करने के लिए नंबर प्लेट की नकल, झूठे घटनास्थल, और गायब फुटेज जैसी स्क्रिप्ट बनाई गई?

या फिर क्या वाकई एक साजिश रचकर दरोगा प्रवास शर्मा की ईमानदारी को मिट्टी में मिलाने का प्रयास हुआ?

फिलहाल, मामला वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में है, जांच जारी है, लेकिन जो बात अब तक सामने आई है वो यह दर्शाती है कि अगर झूठ की इमारत गढ़ी गई थी, तो अब वो खुद अपने ही बोझ से गिर रही है।

# प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की बंदी के खिलाफ ककवन में विरोध बैठक

» गांव-गांव से उठने लगी स्कूल बंदी के खिलाफ आवाज़

» सपा का आरोप शिक्षा छीनने की साजिश कर रही सरकार

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

ककवन (बिल्हौर)। ककवन ब्लॉक की ग्रामसभा मलखरा में बुधवार को प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने के विरोध में एक जागरूकता बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान अनिरुद्ध कोरी ने की जबकि मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के बिल्हौर विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव रहे। विनय यादव ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनने का काम कर रही है। बंद हो रहे स्कूलों से न केवल शिक्षा की पहुँच घटेगी बल्कि शिक्षकों की नौकरियां भी खतरे में पड़ेंगी, जिससे बेरोजगारी और बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ स्कूल बंद करना शिक्षा व्यवस्था के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। ग्राम प्रधान ने भी सरकार को घेरते हुए विरोध जताया। इस दौरान भंते अनिरुद्ध बोधि, प्रदीप पाल, अनुराग सविता, सौरभ पाल, सुनील यादव, गोलू यादव, विजय वर्मा,शादाब खान समेत ग्राम वासी मौजूद रहे।

# केडीए अभियंता के घर में घुसकर मारपीट, लूट और गाली-गलौज

» केडीए के दो सुपरवाइजर समेत तीन पर गंभीर आरोप

»स्वरूप नगर थाने में जूनियर इंजीनियर ने दी तहरीर

**मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया**

**कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के प्रवर्तन अनुभाग में तैनात अवर अभियंता अर्पण सिंह के सरकारी आवास पर बुधवार रात जो हुआ, उसने पूरे विभाग में सनसनी फैला दी। आरोप है कि केडीए के ही दो सुपरवाइजर और उनके एक साथी ने घर में घुसकर जबरदस्ती की, मारपीट, लूटपाट की और अभियंता के दलित नौकर को जातिसूचक गालियां देते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले की एप्लिकेशन थाने में दी गई है।**

घटना बेनाझाबर स्थित सरकारी आवास की है। बुधवार देर रात केडीए सुपरवाइजर बलजीत सिंह और अरुण शुक्ला अपने एक अन्य साथी प्रतीक यादव के साथ अभियंता अर्पण सिंह के आवास पर पहुंचे। सरकारी कामकाज की बात कहकर अंदर घुसे और प्रवर्तन क्षेत्र में फ़अनौपचारिक रूप स काम दिलवाने का दबाव बनाने लगे।

**शराब और पैसे की जबरन मांग**

जब अभियंता ने नियमों का हवाला देते हुए इंकार किया, तो तीनों ने पहले शराब मंगवाने और फिर नकद पैसे देने की मांग की। मना करने पर गाली-गलौज शुरू हो गई। इसी दौरान घरेलू नौकर राहुल दिवाकर ने हस्तक्षेप किया तो उसे जातिसूचक गालियां दी गईं और सिर पर वार कर घायल कर दिया गया।

**मोबाइल और नकदी लूटी, जान से मारने की धमकी**

हमलावरों ने अभियंता के साथ भी मारपीट की, घर में तोड़फोड़ की, पर्दे फाड़ दिए और मेज पलट दी। उन्होंने सिरहाने रखा अभियंता का मोबाइल फोन और करीब 5 हज़ार रुपये नकद उठा लिए। जाते-जाते अभियंता को जान से मारने की धमकी भी दी। सूत्रों के मुताबिक, बलजीत सिंह और अरुण शुक्ला इससे पहले भी केडीए के ही सुपरवाइजर के साथ इसी तरह की घटना कर चुके हैं। पहले साथ में शराब पी और फिर मारपीट की। इस मामले में नजीराबाद थाने में मुकदमा दर्ज है।

**सीसीटीवी में कैद हुई हरकतें**

घटना के बाद अभियंता ने अपने पड़ोसी सहायक अभियंता अतुल राय को फोन कर बुलाया। जब दोनों अभियंता घायल नौकर के साथ घर से निकले, तो देखा कि आरोपी गली के कोने पर खड़े थे। दबाव में आकर उन्होंने अभियंता का मोबाइल लौटाया। वहीं, अभियंता ने स्वरूप नगर थाने पहुंचकर घटना की लिखित तहरीर दी। सामने के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपियों की आवाजाही और उत्पात कैद हो गई है।

मारपीट में घायल केडीए कर्मचारी

पीड़ित जूनियर इंजीनियर अर्पण सिंह

सरकारी आवास के टूटे शीशे

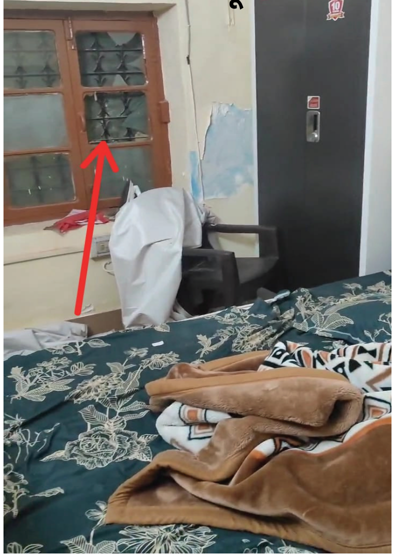

## पुलिस जांच में जुटी, केडीए ने रिपोर्ट तलब की

**स्वरूप नगर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। केडीए प्रशासन ने भी इस गंभीर प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए तीनों आरोपियों से स्पष्टीकरण तलब किया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है, और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।इस मामले में सचिव अभय पांडे ने बताया कि डीएम की मीटिंग में हूं।**

# जातिवादी एडीएम अमित कुमार के खिलाफ सवर्ण समाज में आक्रोश

**प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया**

**कानपुर देहात। कानपुर देहात जिले में तैनात अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार की जातिवादी मानसिकता उजागर होने के बाद सवर्ण समाज के लोगों को आक्रोश है। मामले की शिकायत उच्चस्तर तक हुई है। इनपुट है कि आने वाले समय में एडीएम को जांच का सामना करना पड सकता है।**

FOLLOW UP

**» सोशल मीडिया में छाया रहा कानपुर देहात का मामला,**

**शासन तक पहुंचा एडीएम की हरकत का प्रकरण**

अकबरपुर तहसील के संगसियापुर गांव निवासी प्रभाकर मिश्रा तहसील कर्मी रहे हैं। पत्नी के सुसाइड करने पर मायको वालों की कार्रवाई से कुछ माह के लिए जेल चले गए थे, उस दौरान सस्पेंड किया गया और बाद में बर्खास्त कर दिया गया। इसपर वह हाईकोर्ट गए थे, वहां से उनकी बहाली के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया था। इसके चलते वह बार-बार एडीएम प्रशासन अमित कुमार के पास गए। उस दौरान आरोप लगाया कि उनके साथ जातीय भेदभाव कर टिप्पणी की गई। इसकी शिकायत शासन में की गई है। वहीं, भोगनीपुर तहसील के डीग निवासी अमित पांडेय के वाद निस्तारण में जातिगत भेदभाव कर अधिक जुर्माना लगाया गया। इस तरह से कुछ और प्रकरण हैं जिनमें एडीएम अमित कुमार की भूमिका संदिग्ध है लेकिन शिकायतकर्ताओं के सामने नहीं आने कारण उनका जिक्र नहीं किया जा रहा है। वहीं, अमित कुमार की हरकत के चलते सवर्ण समाज के लोग नाराज दिखे। मै हूं ब्राम्हण सभा के पदाधिकारी अनुरंजन शुक्ला, मनीष शर्मा, मनीष द्विवेदी, अखिलेश द्विवेदी और राजेंद्र

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769 www.swarajindianews.com swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्य: ₹02

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

धर्मांतरण: छांगुर की आलीशान कोठी पर गरजा बुलडोजर » Pg 12

कानपुर, मंगलवार, 08 जुलाई, 2025
वर्ष: 02, अंक: 184, पृष्ठ: 8+4

इनसाइड कानूनन अभी भी विवादों में पनकी मंदिर महंत पद... » Pg03

## जाति देखकर न्याय देते हैं

### कानपुर देहात के एडीएम प्रशासन अमित कुमार!

स्वराज इंडिया Xक्लूसिव

» फरियादियों की शिकायत का निस्तारण की बजाय साहब पर लग रह उत्पीडन करने के लग रहे गंभीर आरोप

» 'सबका साथ सबका विकास' वाली सरकार में एडीएम प्रशासन का हैरान करने वाले कई कारनामे उजागर

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर देहात। केंद्र की मोदी और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार 'सबका साथ-सबका विकास' का नारा देकर देश में अपना उच्चतम कीर्तिमान स्थापित कर रही है। वहीं, कानपुर देहात जिले में एक ऐसे अधिकारी की तैनाती है जो कि जाति देखकर निर्णय लेने के लिए जाने जा रहे हैं। कार्यालय या विभागीय कोर्ट में आने वाले फरियादी को जाति विशेष के आधार पर जलील करते हैं। उनपर इस तरह के गंभीर आरोपों को लेकर कई शिकायतें डीएम से लेकर शासन तक पहुंची हैं। इससे अंदर खाने में हलचल मची हुई है। एडीएम अमित कुमार का पक्ष जानने के लिए सरकारी नंबर पर कॉल की गई लेकिन रिसीव नहीं किया। वहीं, डीएम कानपुर देहात अलोक कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जानकारी की जा रही है।

''पांडेय' सरनेम देख लगाया अधिक जुर्माना

प्रकरण 2

भोगनीपुर तहसील के डीग गांव निवासी अमित पांडेय ने बताया कि परिवार के जीविकापार्जन के लिए गांव के अंदर चाय-समोसा बनाकर बेचते हैं। 31 मई 2024 को पूड विभाग के लोगों ने सौंफ का सेंपल भर लिया था, उसका सेंपल अद्योमानक आया था। यह प्रकरण एडीएम प्रशासन अमित कुमार के यहां चल रहा था। बकौल अमित पांडेय, उसको हर बार तारीख लगाकर बुलाकर परेशान किया जा रहा था। दो माह पहले वह एडीएम प्रशासन के कार्यालय में जाकर अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देकर वाद जल्द निस्तारित करने का अनुरोध किया। इस पर उन्होंने कहा कि ज्यादा जल्दी है क्या, देखता हूं, दो दिन बाद आने को कहा। वह फिर गया तो कार्यालय में वह नहीं मिले, उनके पीए ब्रजेश ने कहा ने 5 हजार रूपए दे दो काम हो जाएगा नहीं तो ऐसे ही चक्कर लगाते रहो। इसके कुछ दिन बाद जानबूझकर उसका उत्पीडन करने के लिए 15 हजार रूपया का जुर्माना लगा दिया गया। सबसे खास बात यह है कि उसी दिन अन्य लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया लेकिन किसी पर 8 हजार और किसी पर उससे भी कम, लेकिन सिर्फ पांडेय होने की वजह से अधिक जुर्माना भी लगाया मानसिक रूप से परेशान भी किया गया। इसपर डीएम आलोक कुमार सिंह को लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया है।

अफसरशाही का ऐसा चेहरा जो व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है

प्रकरण 1

जनपद कानपुर देहात के ग्राम संगसियापुर निवासी प्रभाकर मिश्रा, जो एक सामान्य वर्ग के नागरिक हैं, पिछले चार महीनों से अपनी सेवा बहाली के लिए जिले के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। न्यायपालिका से दोषमुक्त होने के बावजूद प्रशासन की बेरुखी और अपमानजनक व्यवहार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अफसरशाही आज भी आम नागरिक की गरिमा को तार-तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। प्रभाकर मिश्रा ने वर्ष 2025 में 11 मार्च और 30 अप्रैल को सेवा बहाली हेतु औपचारिक रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परंतु कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण तब आया जब मई 2025 में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार से मुलाकात के दौरान उन्हें यह कहकर अपमानित किया गया- 'बार-बार मेरे सामने खड़े हो जाते हो, 35,000 रुपये के लिए मरे जाते हो, कहीं और जाकर क्यों नहीं मरते?' यह कथन किसी भी संवेदनशील और न्यायप्रिय प्रशासनिक व्यवस्था पर सवालिया निशान छोड़ता है। इतना ही नहीं, 3 जून को जब प्रभाकर पुनः कार्यालय पहुंचे तो उन्हें जातिसूचक शब्द कहे गए और उनका उपहास उड़ाया गया। फिर भी, प्रभाकर मिश्रा ने हार नहीं मानी। उन्होंने मांगे गए सभी दस्तावेज और साक्ष्य समय पर प्रस्तुत किए, लेकिन उन्हें बार-बार बुलाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। 20 जून को तो उनके सामने बैठकर वीडियो बनाते हुए मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि वह 'डीएम के बराबर समझते हैं खुद को।' साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर सेवा बहाली से इनकार कर दिया गया, जबकि उक्त आदेश के खिलाफ विशेष अपील उच्च न्यायालय में लंबित है। अब सवाल यह उठता है- क्या सामान्य वर्ग का होना अपराध है? क्या एक दोषमुक्त व्यक्ति को जीवन यापन और गरिमा के अधिकार से भी वंचित किया जा सकता है? प्रभाकर मिश्रा की यह आपबीती न सिर्फ प्रशासनिक संवेदनहीनता की पोल खोलती है, बल्कि यह दर्शाती है कि सिस्टम में कैसे सामान्य वर्ग के गरीब, निरीह नागरिकों को दरकिनार किया जाता है। अफसोस इस बात का है कि एक पढ़ा-लिखा, कानूनी रूप से मुक्त व योग्य नागरिक इसलिए चार महीने से अपमान सह रहा है क्योंकि वह 'सिस्टम' से टकराने का साहस कर रहा है।

अवस्थी ने कहा कि लोकसेवक का इस तरह का आचरण अशोभनीय है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे एक अधिकारी समाज पर सवाल न उठें। प्रकरण की जांच कराए जाने की मांग उठ रही है।

## बैक डेट में प्रभाकर मिश्रा का प्रत्यावेदन निरस्त

स्वराज इंडिया द्वारा खबर प्रकाशन के बाद 7 जुलाई 2025 की तारीख का डीएम आलोक कुमार सिंह की ओर से जारी पत्र के अनुसार प्रभाकर मिश्रा की रिट याचिका संख्या 5380-1996 में जारी आदेश के विरूद्ध विशेष अपील संख्या 1102-2009 योजित की गई जो कि उच्च न्यायालय द्वारा 10-11-20217 को खारिज किया गया था। उसी क्रम में प्रकरण निर्णीत होने के चलते प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया। वहीं, प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि अफसरों ने मनमानी करके प्रकरण का निरस्त कर दिया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जिला प्रशासन एडीएम अमित कुमार का बचाव किया जा रहा है। मै, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के साथ शासन में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मिलकर पूरी बात रखूंगा।

# तिगाई केंद्र प्रथम में सुपोषण कार्यक्रम आयोजित

## गर्भवती महिलाओं और अभिभावकों को दी गई अहम जानकारी

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

**कानपुर देहात। अकबरपुर ब्लॉक के तिगाई केंद्र प्रथम में बुधवार को सुपोषण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्र की कार्यकर्ता शैलेश दीक्षित ने की। इस अवसर पर उन्होंने गर्भवती महिलाओं और बच्चों के अभिभावकों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पोषण के महत्व की जानकारी दी।**

शैलेश दीक्षित ने बताया कि सुपोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को ना सिर्फ उचित पोषण देना है, बल्कि उन्हें सामाजिक गतिविधियों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाले राशन (जैसे - दाल, दलिया और रिफाइंड तेल) को लेकर नई व्यवस्था के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।

कार्यक्रम में बताया गया कि शासन और प्रशासन के निर्देशानुसार अब बिना KYC और फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा प्रमाणीकरण) के किसी भी लाभार्थी को राशन नहीं दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा कई बार जागरूक किए जाने के बावजूद यदि कोई अभिभावक आवश्यक प्रमाणीकरण नहीं कराता है, तो राशन न मिलने की जिम्मेदारी स्वयं उसकी होगी।

कार्यक्रम में राममूर्ति, सियाकली, सबाना, प्रदीप समेत कई लाभार्थी और ग्रामीण उपस्थित रहे। आंगनबाड़ी केंद्र की ओर से यह भी अपील की गई कि सभी अभिभावक समय रहते अपनी KYC और फेस प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण सामग्री मिलने में कोई बाधा न हो।

## सम्पादकीय

# राजनीतिक एकजुटता व जन संकल्प

हाल के दिनों में हिमालयी राज्यों खासकर हिमाचल व उत्तराखंड में अतिवृष्टि और बादल फटने की घटनाओं में जिस तेजी से पुनरावृत्ति हुई है, उसे मौसम के चरम के रूप में देखे जाने की जरूरत है। हालांकि, तात्कालिक जरूरत आपदा प्रभावित जिलों में राहत, बचाव व पुनर्वास के प्रयासों में तेजी लाने की है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत मौसम के चरम के बीच अचानक आती बाढ़ और बार-बार बादल फटने के कारणों को भी समझने की है। हाल ही में, इन्हीं मुद्दों की तरफ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी ध्यान खींचा है। निस्संदेह, इन कारणों की पड़ताल के लिए विषय विशेषज्ञों की सहायता लेना भी जरूरी है। पिछले दिनों हिमाचल में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री ने उन उपायों की सूची पर चर्चा की, जिन्हें तत्काल लागू करने की आवश्यकता है। इन उपायों में नदियों में अवैज्ञानिक तरीके से मलबा फेंकने की जांच, नियमित मौसम अपडेट देना और नदी-नालों से कम से कम सौ मीटर की दूरी पर घरों का निर्माण करना शामिल है। लेकिन इसके प्रभावी लक्ष्य तभी हासिल किए जा सकते हैं जब इस बाबत किसी ठोस योजना को अमलीजामा पहनाया जाए और साथ ही नीतियों के क्रियान्वयन की समय सीमा निश्चित की जाए। निश्चित रूप से मौजूदा संकट को देखते हुए युद्धस्तर पर काम करने की जरूरत है। वह समय चला गया जब सरसरे आदेश दिये जाते और सिफारिशें की जाती थीं। कानूनों और नियमों की अनदेखी के खिलाफ सभी एजेंसियों को तालमेल बैठाकर इस दिशा में अभियान चलाने की जरूरत है। वनों की अवैध कटाई, अनियोजित निर्माण और अवैज्ञानिक विकास प्रथाओं पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। इसके लिये सरकारी मशीनरी को मिशन मोड में काम करने की जरूरत होगी। जिसके लिये मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। भले ही राज्य की सत्ता में दो दलों का वर्चस्व हो और उनकी विचारधाराओं में टकराव रहा हो, लेकिन इस मुद्दे पर एकजुट होकर संकट का मुकाबला करने की जरूरत है।

निश्चय ही हाल के वर्षों में पहाड़ विरोधी विकास ने हिमालयी राज्यों की अस्मिता को आहत किया है। हिमालयी राज्यों में लोग पहाड़ों के मूल चरित्र में हस्तक्षेप करने वाले विकास की विसंगतियों की कीमत चुके रहे हैं। अब चाहे बड़े बांध हों या फोर लेन सड़के हों। निस्संदेह, विकास हर राज्य की प्राथमिकता है, लेकिन विकास योजनाओं को पहाड़ों की जरूरत के मुताबिक बनाया जाना चाहिए। इन राज्यों में स्थितियां विकट हैं और हालात और खराब होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भूस्खलन की लगातार बढ़ती घटनाएं और दरकती सड़कें इसकी बानगी मात्र हैं। कुल मिलाकर पहाड़ों के अस्तित्व पर संकट बढ़ा है। निस्संदेह, मौजूदा रणनीति और नीतियां इस संकट से निबटने में सक्षम नहीं हैं। सत्ता में बैठे लोगों के लिये जरूरी है कि वे मौसम विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों और क्षेत्र के अनुभवी लोगों से राय लें। पहाड़ हमारी आवश्यकता तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन वे इंसान की विलासिता का बोझ सहन करने को तैयार नहीं हैं। निश्चित ही आधुनिकता की आंधी में संयम का जीवन और आवश्यकताओं को सीमित करना कठिन कार्य है, लेकिन बचाव का संभवतः अंतिम उपाय यही है। बहुमंजिला इमारतों को सीमित करना, जल निकासी की समुचित व्यवस्था और निर्माण से पहले जमीन की क्षमता का आकलन करना जरूरी हो जाता है। नदियों में होने वाले अवैध खनन को रोकना भी उतना जरूरी है, जितना जंगलों का कटान रोकना जरूरी है।

# संकट से सबक लें भारतीय विश्वविद्यालय

सोमेश गोयल

**हार्वर्ड का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक भलाई के लिए उच्च-स्तरीय शिक्षा और शोध को बढ़ावा देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना और अन्याय और अमानवीय कृत्यों का विरोध करने वाली उदार विचारधारा को बढ़ावा देना है।ज्ञान मानव चेतना और मेहनत से विकसित एक सतत सामाजिक शक्ति है, जो प्रारंभ में निःशुल्क साझा और अनुकरण द्वारा बढ़ता रहा। समय के साथ, इसे आर्थिक और राजनीतिक संसाधन के रूप में संगठित किया गया, जिससे इसका उपयोग एक नियंत्रित यंत्र की तरह होने लगा। ज्ञान सामाजिक विरासत और जिम्मेदारी है।**

ज्ञान साझा करने की नियंत्रित प्रणाली को शिक्षा प्रणाली कहा जाता है, जिसे राज्य की कानून व्यवस्था के तहत योजनाबद्ध किया गया है। आज इसे उद्योग और वित्तीय क्षेत्र धन उत्पादन के साधन के रूप में भी नियोजित किया जाता है। शिक्षा प्रणाली में ज्ञान के प्रसारण, अनुसंधान और विकास को राज्य सत्ता के प्रतिनिधि अपनी नीतियों के अनुसार नियंत्रित करते हैं, ताकि वे अपने हितों की सेवा कर सकें। विज्ञान, औद्योगिक क्रांति और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदय के बाद ज्ञान भी बाजार में एक वस्तु बन गया है। औद्योगीकरण, सामाजिक संरचना और श्रम परिवर्तन की जरूरत ने जन शिक्षा पर जोर बढ़ाया है। राजतंत्र से लोकतंत्र और उदार लोकतंत्र की ओर बदलाव ने मानव अधिकारों, बहुसंस्कृति, समानता और समावेश को उदार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मानवीय पहलू बनाया है।संयुक्त राज्य अमेरिका उदार पूंजीवादी नीतियों के साथ दुनिया के प्रमुख उदार लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, जहां हर मूल के व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने और योग्यता के आधार पर नागरिकता पाने का अवसर मिलता है। इसकी शिक्षा प्रणाली विश्व की श्रेष्ठ प्रणालियों में से एक मानी जाती है, जो उच्चतम कौशल और ज्ञान प्रदान करती है, जिसका उदाहरण हार्वर्ड विश्वविद्यालय है।

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व वाली रूढ़िवादी पार्टी ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद उदार आव्रजन और शिक्षा नीतियों पर प्रतिबंध लगाने शुरू किए। ट्रम्प प्रशासन ने इस्राइल-विरोधी प्रदर्शनों के दौरान यहूदी-विरोधी भावना रोकने में विफल रहने का आरोप लगाकर हार्वर्ड और अन्य विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई की है। उनसे विद्यार्थी प्रवेश और फैकल्टी भर्ती डेटा साझा करने और समावेशी कार्यक्रम बंद करने को कहा गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रम्प प्रशासन के डीईआई कार्यक्रमों को बंद करने और प्रवेश-भर्ती डेटा साझा करने के आदेश को मानने के बजाय अदालत में चुनौती दी है। इसके जवाब में संघीय सरकार ने हार्वर्ड की 2.2 बिलियन डॉलर की शोध अनुदान राशि रोक दी है, कर-मुक्त दर्जा वापस लेने और छात्र विनिमय प्रमाणपत्र रद्द करने के आदेश जारी किए हैं।सरकारी प्रतिबंधों से हार्वर्ड को वित्तीय संकट के साथ-साथ विदेशी छात्रों के एफ और जे विज़ा नामांकन पर भी असर पड़ता, लेकिन हार्वर्ड ने अपने मूल्यों पर अडिग रहते हुए इन आदेशों को अदालत में चुनौती दी।

अदालत ने सुनवाई तक सरकारी आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसने ट्रम्प-हार्वर्ड विवाद और अमेरिकी शिक्षा प्रणाली के भविष्य को दुनिया भर में बहस का विषय बना दिया है। ट्रम्प प्रशासन का लक्ष्य परस्पर विरोधी हितों का राजनीतिकरण करना, उदार विचारधाराओं के प्रसार को रोकना और संकीर्ण राष्ट्रवादी हितों को पूरा करना है, जबकि हार्वर्ड का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक भलाई के लिए उच्च-स्तरीय शिक्षा और शोध को बढ़ावा देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना और अन्याय और अमानवीय कृत्यों का विरोध करने वाली उदार विचारधारा को बढ़ावा देना है।वैश्विक स्तर पर हार्वर्ड के पूर्व छात्रों ने 146,429 नौकरियां पैदा की हैं। हार्वर्ड के कई पूर्व छात्र अपने देशों में शासक या नौकरशाह बन गए हैं।

# विभाजित परिदृश्य में भारत की संयमपूर्ण नीति

## उदारतापूर्ण व्यवहार

डा0 सुधीर कुमार

**ऐसे वक्त जब दुनिया के देशों में प्रभुत्व की होड़ मची है, भारत आजादी के बाद के सफर में अपनी रीति-नीति पर कायम है। जब वैश्विक संस्थाएं बिखर रही हैं - डब्ल्यूटीओ कमज़ोर पड़ा है, संयुक्त राष्ट्र मौन है, भारत संयम अपनाए हुए है। ऑपरेशन सिंदूर का भी संदेश है कि भारत चीन-पाक के तनाव बढ़ाने के खेल में नहीं फंसेगा, लेकिन पीछे भी नहीं हटेगा।**

**बढ़ते तनावों और पीछे हटती सच्चाइयों के युग में, भारत अपने शांत विमर्श के साथ, अपनी आज़ादी के 80 वर्ष पूरे करने जा रहा है। हमारी यात्रा एक ऐसा वृत्तांत रही है, जिसे फिर से बताने की ज़रूरत है - भले ही अपनी सौवीं वर्षगांठ की परिकल्पना, शक्ति का विस्तार करने में नहीं, बल्कि अपने उद्देश्यों को और गहराई देने में है।**

जहां अन्य राष्ट्रों में प्रभुत्व बनाने के लिए होड़ मची है, भारत अपनी राह पर कायम है- विचारधारा में धंसा हुआ नहीं, बल्कि सभ्यतागत नैतिकता की गहरी जड़ों से जुड़ा, जिसे हम 'युमैनशिप' अर्थात धर्मनीति के नाम से जानते हैं- सतत राष्ट्रीय आचार संहिता, स्मृति द्वारा आकार पाई, समदृष्टि सहित और मूलतः संयम वाली। यह कोई जुमला नहीं; हमारा वह व्यवहार है, जिसे हम तब भी कायम रखते हैं जब कोई न देख रहा हो और कैसे हम सबके सामने होने के बावजूद खुद को रोक लेते हैं। यह नैतिकता हमने अपने सबसे प्राचीन शब्दकोष से पाई है।दुनिया युद्ध और इसकी चेतावनियों के बीच डगमगा रही है। गाजा खून में सना है; यूक्रेन बिखरने की कगार पर है; ईरान और इस्राइल अपने संयम की सीमाएं नाप रहे हैं। व्यापार बल-प्रयोग का औजार बन गया है। जलवायु परिवर्तन के खतरे को हथियार बनाया जा रहा है। तकनीक उपकरण और ख़तरा, दोनों बन गई है। परमाणु संयम, लापरवाही भरी बयानबाज़ी में बदल गया है। संयुक्त राष्ट्र पंगु हुआ पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति के स्थाई सदस्य देश तभी कार्रवाई करते हैं, जब उनके हित आपस में मिलें। संतुलन का भरोसा देने वाले तंत्र को साजिशन मामलों से अलग रखा जा रहा है।1948 से 2025 तक, हमारे विकल्प सतत कहानी बताते हैं। हम लाहौर की दहलीज़ पर जाकर थम गए, जीता हुआ हाजी पीर इलाका लौटा दिया, और पाकिस्तानी सेना को दूर तक खदेड़ने के बावजूद मुज़फ़्फ़राबाद पर कब्ज़ा नहीं किया। सीमा पार किए बिना कारगिल पर फिर से कब्ज़ा कर लिया। हमने ढाका को आज़ाद करवाया और बाद में उन 90,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को स्वदेश भेजा, जिनके साथ जिनेवा संधि के तहत उदारतापूर्ण व्यवहार किया गया। जोर-ज़बरदस्ती में बदल गया जब चीन, जो खुद प्राचीन सभ्यता है और जिसके साथ हम शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व चाहते थे, उसने वार्ता की बजाय धोखा चुना। युद्ध त्वरित रहा। जब धूल छंटी, तो एक सवाल ज़रूर उठा ः चीन ने अपनी शिष्टता तज क्या पाया और सह-अस्तित्व की नैतिकता त्यागकर क्या खोया? भरोसा टूट गया।लॉर्ड कर्जन ने 1907 में ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय में 'फ्रंटियर्स' नामक सालाना व्याख्यान में कहा था ः 'सहमति वाली स्पष्ट सीमारेखा की बजाय असहमति वाली सीमाओं से ज्यादा हासिल किया जा सकता है'। एक सदी बाद, लगता है कि चीन ने वह सिद्धांत आत्मसात कर लिया। आज, भारत के संयम की परीक्षा और दिखाए गए दृढ़ संकल्प के प्रदर्शन के साथ, चीन को खुद सामने आते नहीं पा रहे, बल्कि वह खेल कर रहा है - खुद पीछे रहकर किसी और से जोर-ज़बरदस्ती करवाने वाले की भूमिका में। इस नाटक का पर्दाफाश करने में ऑपरेशन सिंदूर पहला उदाहरण रहा। यह चीन और उसका मुखौटा बने पाकिस्तान के लिए एक संदेश भी था ः जहां भारत तनाव को विस्तार देने के उनके खेल में नहीं फंसने वाला है वहीं पीछे भी नहीं हटेगा। हाथी सब याद रखता है।

# चौखंडी वालों से किस बात की नाराजगी है प्रधान जी..?

कानपुर नगर से
स्वराज इंडिया
संवाददाता
रिज़वान कुरैशी

» विकास की राह में अटी पड़ी है गंदगी

» गांव वालों का आरोप-प्रधान का सौतेला व्यवहार,सिर्फ अपने गांव को दे रहे लाभ

» सीसी सड़क के ऊपर बिछवा दी गई सीमेंटेड ईंट

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला चौखंडी गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव की टूटी-फूटी गलियां, बजबजाती नालियां और स्कूल के बाहर लगे कचरे के ढेर इस बात की गवाही देते हैं कि यहां विकास की एक किरण तक नहीं पहुँची है। काली कमाई के चक्कर में गांव की एक ठीकठाक सीसी सड़क के ऊपर सीमेंटेड ईंटे बिछवाकर लाखों रुपए हजम कर लिए जाने का आरोप है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान जानबूझकर चौखंडी को नज़र अंदाज़ कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधान को लगता है कि चौखंडी गांव से उन्हें अपेक्षित वोट नहीं मिला, इसलिए अब विकास कार्यों से भी गांव को वंचित रखा जा रहा है। गौरतलब है कि उक्त ग्राम पंचायत में तीन मजरे शामिल हैं, लेकिन विकास कार्य सिर्फ प्रधान के निवास वाले बरौली गांव में ही कराए जा रहे हैं। चौखंडी गांव की गलियों में गंदगी, जलभराव और सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति अब स्थायी समस्या बन चुकी है।

चौखंडी स्कूल के बाहर सड़कों पर गंदा पानी और घूरा पड़ा है, जिससे बच्चों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई ।नालियों की सफाई न होने से गालियों में गन्दा पानी बहता है। बारिश के महीनों में यह समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है।

पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही गांव-गांव दावेदार सक्रिय हो गए हैं। गांवों में खेमेबंदी शुरू हो गई है। प्रधान जी ने अपने गांव में क्या-क्या विकास कार्य कराए हैं। लोगों की उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं और कितनी अधूरी रह गई हैं। नए दावेदार किन मुद्दों के साथ खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं। इन सबका लेखा जोखा लेकर आपका लोकप्रिय अख़बार दैनिक स्वराज इंडिया जल्द ही आपके बीच हाजिर होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि गांव की असल तस्वीर सामने आए और शासन-प्रशासन तक लोगों की आवाज़ पहुँचे।ताकि तस्वीर बदले। तो फिर आप भी तैयार रहिए अपने गांव के आंकड़ों के साथ। हम खुद चलकर आयेंगे आपके दरवाजे तक.....

## सबसे स्वच्छ-सुंदर हमारा गांव!

गांव के नेकराम ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए चुटकी ली कहा कि सबसे स्वच्छ सुंदर गांव हमारा है, ये देखिए...सड़क पर पानी बह रहा है। और नाली कहां है ये खुद नाली को भी नहीं पता। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले दो सालों से कोई सफाईकर्मी गांव में झांकने तक नहीं आया।

## बरौली बिल्कुल टन्न डाली हई, हिन छिछालेदर पड़ी है!

गांव के जहांगीर ने कहा कि बरौली गांव का हाल देख लो, बिल्कुल टन्न डाली हई। हिन छीछालेदर पड़ी है चारों ओर। चुनाव में वोट मँगै आ जात हैं, बाकी समय इनका गांव की याद भी नहीं आती। जहांगीर ने तंज कसते हुए ग्राम प्रधान को नटवरलाल तक कह डाला।

## सख्त हुकूमत के बावजूद, गांव की दशा जस की तस

गांव के बाबू राम कहते हैं..हई! इतना सख्त शासन है, फिर भी गांव की हालत देखौ... पूछो मत!ना कोई देखन वाला,ना सुनन वाला। अफसर तो आने से रहे। कालोनी तौ ओही पावत है, जेखे लगे पैसा होत है।

## जियो चाहे मरो, काहू को कउनो वास्ता नहीं!

गांव के एक बुजुर्ग कहिन जब प्रधानी का चुनाव आवत है,तौ सब हाथ जोड़त फिरत हैं। फेर जीत गवा कि भूल जात हैं गांव का रस्ता। न देखन वाला,न सुनन वाला कोई... जियो चाहे मरो, कउनो को कउनो मतलब नाहीं।

चौखंडी स्कूल गेट का हाल

नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं ग्रामीण

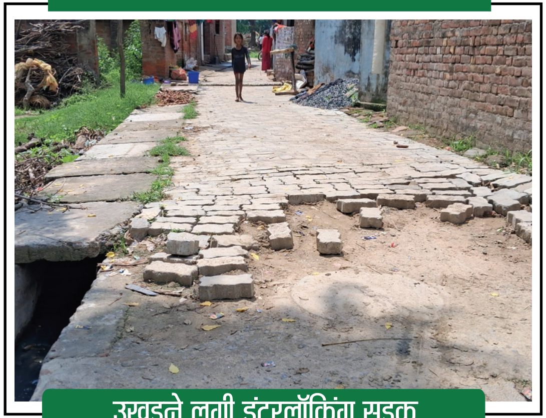

उखड़ने लगी इंटरलॉकिंग सड़क

# वसूली के आरोपी दारोगा हुआ लाइन हाजिर

» एसएसपी अयोध्या डॉ गौरव ग्रोवर ने सोसल मीडिया पर वायरल वीडियो पर की कार्यवाही

स्वराज इंडिया संवाददाता

अयोध्या। श्रद्धा, धर्म और मर्यादा की धरती अयोध्या अब मुट्ठी में बंद वसूली के वायरल वीडियो से शर्मसार है। लता चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी जिन पर थी, वे अब वसूली करते कैमरे में कैद हो गए।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक ट्रैफिक दारोगा वाहन चेकिंग के नाम पर एक ड्राइवर से चुपके से मुट्ठी में पैसे ले रहा है। दरोगा की यह नकद न्याय प्रणाली उस वक्त रंगे हाथों पकड़ी गई, जब एक जागरूक युवक ने वीडियो बना लिया और दरोगा से पूछ डाला मुट्ठी खोलो, कितना लिया?

वीडियो में दरोगा का चेहरा, उसकी झेंप और बगलें झांकती नैतिकता सब साफ दिख रही हैं।

ये मामला कोतवाली अयोध्या के अंतर्गत लता चौक का बताया जा रहा है, जहां ट्रैफिक पुलिस की यह करतूत अब चर्चा का विषय बन चुकी है।

# कानपुर मथुरी मोहाल में हफ्तों से जलभराव, जनता में फूटा गुस्सा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। शहर के वार्ड 106 अंतर्गत मथुरी मोहाल इलाके में आमजन जीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है। केतकी देवी धर्मशाला के ठीक बगल में स्थित सड़क और नाली में पिछले कई हफ्तों से लगातार गंदा पानी भरा हुआ है। नाली की सफाई न होने और बारिश के पानी की निकासी न होने के कारण यह जलभराव अब गंभीर समस्या बन चुका है।स्थानीय लोगों के अनुसार, जलभराव से केवल राहगीरों को ही नहीं, आसपास के दुकानदारों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव में मच्छरों का प्रकोप बढ़ चुका है जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। बदबू और गंदगी के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है।

क्षेत्रीय निवासियों ने बताया कि उन्होंने कई बार पार्षद को समस्या से अवगत कराया, लेकिन न तो कोई स्थलीय निरीक्षण हुआ और न ही कोई सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की गई। पार्षद की लगातार अनुपस्थिति और नगर निगम की उदासीनता से जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।स्थानीय नागरिक ने बताया, हम रोज़ इस गंदगी से होकर निकलते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन न पार्षद आए, न कोई सफाईकर्मी। हमें लगता है जैसे चुनाव के बाद सबने मुंह मोड़ लिया है।लोगों की मांग है कि नगर निगम इस मुद्दे पर त्वरित संज्ञान ले और क्षेत्र में जल निकासी एवं सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करे। अब सवाल उठाता है कि आखिर जनता की समस्याओं पर जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की चुप्पी कब तक बनी रहेगी? क्या विकास केवल कागज़ों पर ही रह जाएगा?क्षेत्रिय पार्षद से बात करने पर पार्षद ने बताया कि मेट्रो द्वारा जो बिल्डिंगों के नीचे सीमेंट का काम हुआ हैं उसी से कई जगह नालियां जाम हो गई हैं उसी से ये सब समस्या उत्पन्न हो रहीं जिसे जल्द सुधार किया जाएगा अभी होटल अपोलो के पास सुतर खाना में काम चल रहा हैं जैसे ही काम पूरा होगा उसके बाद यहां पर भी कार्य चालू होगा।

# सपा के प्रांतीय नेता वीरसेन यादव ने कार्यकर्ताओं से मिलकर सुनी समस्याएं

» भोगनीपुर स्थित जन संपर्क कार्यालय में लगाई चौपाल

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

**कानपुर देहात। जनसम्पर्क कार्यालय भोगनीपुर में समाजवादी पार्टी के प्रांतीय नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष वीरसेन यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। श्री यादव ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनीं और कई मामलों में संबंधित अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर त्वरित समाधान का आश्वासन भी दिया।**

कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने श्री यादव को माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि आगामी चुनावों की तैयारी में अभी से जुट जाएं, कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है।

इस मौके पर भोगनीपुर विधानसभा प्रभारी तुलाराम कोरी का भी कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी सोने लाल यादव, महिला सभा की पूर्व अध्यक्ष नसरीन अख्तर, जिला उपाध्यक्ष अकरम कुरैशी, नगर उपाध्यक्ष महेन्द्र सिंह बड़े ठाकुर, कैप्टन रामशंकर प्रजापति, प्रधान राकेश यादव, गजेन्द्र प्रताप सिंह, रामसनेही कटियार, मोनू विश्वकर्मा, रामविलास निषाद, धर्म सिंह, पूर्व प्रधान महाराज सिंह, रमेश यादव,

पूर्व सभासद नफीस राईन, पार्षद एवं युवा नेता राजू यादव, पुष्पेन्द्र सिंह, मोहित गुप्ता, सुजीत पाल, पिछड़ा वर्ग के जिला उपाध्यक्ष छोटे दरोगा जी, उदयनारायण सिंह, सुनील यादव,

ब्रजेश गौतम, अजीत यादव, अखिलेश यादव, प्रेमपुर सहित अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की मजबूती के लिए एकजुट होकर मेहनत करने का संकल्प लिया।

# टप्पेबाजों ने रूरा में महिला को बनाया लूट का शिकार

» काशीपुर जा रही महिला के बैग से निकाली नगदी व कीमती जेवरात, पुलिस को भनक तक नहीं

» लगातार वारदातों से सहमे ग्रामीण, पुलिस की नाकामी पर उठे सवाल

**स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो**

**कानपुर देहात। रूरा थाना क्षेत्र इन दिनों अपराधियों के लिए मुफ़ीद अड्डा बनता जा रहा है। लूट, टप्पेबाजी और चोरी जैसी घटनाएं अब आम हो गई हैं, लेकिन पुलिस की सुस्ती अपराधियों के हौसले बुलंद कर रही है। ताज़ा मामला रूरा कस्बे के पास का है, जहां एक महिला ऑटो में बैठकर अपने गांव काशीपुर जा रही थी, तभी वह टप्पेबाजों का शिकार बन गई।**

जानकारी के अनुसार, पीड़िता बाबरपुर से ऑटो में सवार होकर काशीपुर गांव जा रही थी। रास्ते में कुछ पहले से मौजूद शातिर टप्पेबाजों ने महिला को भरोसे में लिया और बातचीत के बहाने उसे भटकाते रहे। महिला के बैग में रखे करीब दो लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात और नगदी पर उनकी नजर थी। जैसे ही मौका मिला, टप्पेबाजों ने बैग से पूरा सामान निकाल लिया और ऑटो से उतरकर मौके से फरार हो गए।महिला को अपने साथ हुई ठगी का पता तब चला जब वह काशीपुर पहुंची और बैग खोलकर देखा। परिजन जब उसे लेकर थाने पहुंचे तो वहां भी उन्हें तात्कालिक राहत या कार्यवाही का कोई आश्वासन नहीं मिला।

मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।स्थानीय लोगों का कहना है कि रूरा थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। हर सप्ताह कहीं न कहीं किसी न किसी को निशाना बनाया जा रहा है। खासकर महिलाएं, बुजुर्ग और अकेले सफर करने वाले व्यक्ति लगातार अपराधियों के निशाने पर हैं। बावजूद इसके थाना पुलिस की सक्रियता न के बराबर है। न तो गश्त हो रही है, न ही टप्पेबाजों के गिरोह पर शिकंजा कसने की कोई तैयारी दिख रही है।ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि रूरा क्षेत्र में गश्ती बढ़ाई जाए, सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं और बाजार-चौराहों पर संदिग्धों की निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की जाए, जिससे घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 | **Email:** swarajindia2023@gmail.com | **Mob:** 7800009853, | **Website:** www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

# पीड़िता के बहू बेटे पुलिस में फिर भी नहीं हो रही थाने में सुनवाई

## इज्जत बचाने को दौड़ती रही महिला, अकेलेपन देखकर अराजक तत्वों ने की नाजायज हरकत

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

कानपुर देहात। जिले के डेरापुर थाने के अंतर्गत मिर्जापुर गाँव की बुजुर्ग महिला शिव देवी पर एक युवक द्वारा की गई अश्लील हरकतों और पीछा करने की घटना ने गाँव में सनसनी फैला दी है।शिव देवी, जो कि मिर्जापुर खुर्द गाँव की रहने वाली हैं, अकेली घर पर थीं। उनके पति शिवरतन सिंह औरैया वीज़ा बनवाने गए हुए थे, जबकि दोनों बेटे और बहुएं पुलिस विभाग में सेवा दे रहे हैं। घटना के समय महिला खेतों के पास जानवरों को देख रही थीं, तभी ग्राम निवासी जगदीश सिंह पुत्र सिताब सिंह ने मौका देखकर बदनीयती से महिला की ओर झपटने की

कोशिश की।

शिव देवी ने किसी तरह खुद को बचाते हुए खेत से भागकर इज्जत तो बचा ली, लेकिन आरोपी ने रास्ते में गंदी-गंदी गालियाँ देते हुए पीछा किया। महिला की सूचना पर 112 नंबर पुलिस टीम मौके पर पहुँची, परंतु तब तक आरोपी फरार हो चुका था।घटना के बाद डरी-सहमी महिला ने थानाध्यक्ष डेरापुर को शिकायती पत्र सौंपते हुए मांग की है कि जगदीश सिंह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आगे किसी महिला की इज्जत खतरे में न पड़े

पीड़िता ने बताया कि अकेलेपन का फायदा उठाकर आरोपी ने इस शर्मनाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की, जिससे वह मानसिक रूप से भी अत्यंत परेशान हैं।

अब देखना होगा कि डेरापुर पुलिस इस मामले में कितनी तेजी से न्याय दिलाने का काम करती है। गाँव की महिलाओं ने भी इस घटना पर नाराज़गी जताई है और आरोपी के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।

# गांवों में गंदगी का साम्राज्य, सफाईकर्मी नदारद, अफसर बेखबर

## » कागज़ों में संचारी रोग अभियान सफल, ज़मीनी हालात बद से बदतर

## » नालियों से बजबजा रही बदहाली, ग्रामीण बोले ब्लॉक अफसर सिर्फ जी हुजूरी में व्यस्त

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

कानपुर देहात। विकासखंड मलासा की विजयसिंहपुर पंचायत के अंतर्गत ग्राम अकोढ़ी का माजरा महीनों से सफाई संकट से जूझ रहा है। गांव की नालियां पूरी तरह चोक हो चुकी हैं और चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गांव में तैनात सफाईकर्मी लंबे समय से गायब है, जिससे नालियों से निकला गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है और कीचड़ भरे रास्तों ने ग्रामीणों की दिनचर्या दूभर कर दी है।

स्थानीय निवासी हर्ष अवस्थी, सतीश पांडेय, सतेंद्र सविता, रूपेश तिवारी व सोनल पांडेय का कहना है कि उन्होंने कई बार ग्राम सचिव से लेकर ब्लॉक स्तर तक शिकायतें कीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थिति यह है कि हर ओर बदबू, गंदगी और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है।

सरकार भले ही संचारी रोग नियंत्रण को लेकर अभियान चला रही हो, लेकिन इस गांव में वह महज कागज़ों तक ही सीमित नजर आता है। न तो किसी प्रकार की नियमित सफाई हो रही है,

न ही छिड़काव या अन्य रोग नियंत्रण की कोई कार्रवाई दिख रही है। अफसरों की उदासीनता और सफाईकर्मियों की गैरहाजिरी ने हालात को बद से बदतर बना दिया है।ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई,

तो बरसात में यह गंदगी जानलेवा बन सकती है। जब प्रभारी एडीओ पंचायत मलासा अमिता मिश्रा से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो संपर्क नहीं हो सका। अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागेगा और गांव को गंदगी के दलदल से बाहर निकालेगा।

# नोडल अधिकारी ने जन-जन तक भेजा वृक्षारोपण का संदेश

## » ग्राम कोरारी, फत्तेहपुर रोशनाई व आयुष हॉस्पिटल में किया पौधारोपण, आमजन से जुड़ने की अपील

## आयुष चिकित्सालय का किया निरीक्षण, मरीजों से बातचीत कर दी बेहतर इलाज की हिदायत

**स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो**

कानपुर देहात। पर्यावरण संरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृहद वृक्षारोपण अभियान में मंगलवार को महानिदेशक आयुष एवं नोडल अधिकारी वृक्षारोपण मानवेंद्र सिंह ने जनपद कानपुर देहात में कई स्थलों पर पौधारोपण कर अभियान को गति दी। उन्होंने ग्रामीणों व अधिकारियों के बीच जाकर न सिर्फ पौधे लगाए, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता का भी संदेश दिया।

नोडल अधिकारी ने विकासखंड सरवनखेड़ा के ग्राम कोरारी, अकबरपुर तहसील के आयुष हॉस्पिटल शहजादपुर, तथा फत्तेहपुर रोशनाई में खुद पौधारोपण किया और लोगों को इसके संरक्षण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा केवल पौधे लगाने की नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित और संरक्षित करने की है। इसी क्रम में उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि जियो टैगिंग सहित सभी आवश्यक जानकारी समय से अपलोड की जाए और पौधों की नियमित निगरानी की जाए।

निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने ग्रामीणों से संवाद कर अपील की कि जो भी वृक्ष वितरित किए जा रहे हैं, वे केवल सजावटी नहीं, आपके जीवन रक्षक हैं इन्हें लगाकर परिवार की तरह पालें। इस मौके पर ग्रामीणजनों ने भी उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई।

इसके अतिरिक्त उन्होंने आयुष चिकित्सालय शहजादपुर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जनरल वार्ड, महिला वार्ड, दवा वितरण कक्ष व आयुष वन का स्थलीय अवलोकन किया। उन्होंने मरीजों से बात कर उपचार की स्थिति जानी और मौजूद चिकित्सकों को निर्देश दिए कि मरीजों को बेहतर और समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराया जाए। अस्पताल की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए।

इस मौके पर परियोजना निदेशक वीरेंद्र सिंह, डीसी एनआरएलएम गंगाराम वर्मा, एसडीएम अकबरपुर अवनीश कुमार, एडीओ (आईएसबी) विमल सचान, ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप शुक्ला, सुधीर अवस्थी, दीपक यादव, जूनियर हाई स्कूल कोरारी की शिक्षिका श्रीमती शिल्पी श्रीवास्तव, तथा स्कूली बच्चे मौजूद रहे और सभी ने वृक्षारोपण में भागीदारी कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली।

# लाइट ट्रिपिंग से परेशान जबरीखुर्द के ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

## बिजली विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

**निंदूरा (बाराबंकी)। कुर्सी विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जबरीखुर्द में जर्जर विद्युत तारों और लंबे समय से ठप बिजली आपूर्ति से परेशान ग्रामीणों का सब्र गुरुवार को जवाब दे गया। हफ्तों से बिजली की समस्या झेल रहे ग्रामीणों ने विभागीय लापरवाही से क्षुब्ध होकर जोरदार प्रदर्शन किया और जल्द समाधान की मांग की।**

ग्रामीणों का कहना है कि बीते दो वर्षों से गांव में जर्जर और जोड़-तोड़ कर लगाए गए तारों से बिजली आपूर्ति की जा रही है। इससे जहां लो-वोल्टेज की समस्या बनी रहती है, वहीं चिंगारी निकलने से हादसे का खतरा भी लगातार बना रहता है।

बीते सप्ताह तार में आग लगने से तार जलकर जमीन पर गिर गया, जिससे पूरे गांव की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है और ग्रामीण अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं।

प्रशासन की अनदेखी से नाराज़ ग्रामीण प्रदर्शन में शामिल ग्रामीण कफील अहमद, शरीफ अहमद, नियाज़, सकील, रफीक सहित अन्य उपभोक्ताओं ने बताया कि दशकों पुराने तार घरों और रास्तों के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये तार कभी भी गिर जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तार गिरने की सूचना देने पर उपकेंद्र के जेई और अन्य अधिकारी फोन नहीं उठाते, और यदि किसी तरह सूचना पहुंच भी जाए तो दो-दो दिन तक तार नहीं जोड़े जाते।

बार-बार मिल रहा केवल आश्वासन

ग्रामीणों ने बताया कि कई बार अधिकारियों से मिलकर शिकायत की जा चुकी है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिलता है, काम शुरू नहीं होता। एसडीओ कुर्सी विद्युत उपकेंद्र सर्वेश कुमार पाल ने जानकारी दी कि जर्जर तारों को बदलने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि यह आश्वासन उन्हें कई महीनों से मिल रहा है।गांव के लोगों ने बिजली विभाग से तत्काल कार्रवाई कर जर्जर तारों को बदलने और बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

# लोधेश्वर महादेवा सावनी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में

## उपजिलाधिकारी ने दिया सुरक्षा व सुविधा व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश

**अंकित यादव स्वराज इंडिया**

रामनगर (बाराबंकी)। पवित्र श्रावण मास के अवसर पर लोधेश्वर महादेवा में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध सावनी मेला 11 जुलाई से आरंभ होने जा रहा है। मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। मंगलवार को उपजिलाधिकारी विवेक शील यादव, तहसीलदार विपुल कुमार सिंह और थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडे ने स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया और सभी कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी ने बैरिकेडिंग में इस्तेमाल हो रही पतली और कमजोर बल्लियों को देखकर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने संबंधित ठेकेदार और जिला पंचायत के अवर अभियंता को निर्देशित किया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत और मोटी बल्लियां तत्काल लगवाई जाएं। उन्होंने दो टूक कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान ग्राम प्रधान राजन तिवारी, चौकी इंचार्ज महादेवा संतोष कुमार त्रिपाठी, सचिव रविंद्र कुमार, लेखपाल संतोष कुमार, नूर मोहम्मद, गुरशरण सहित कई संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

**जल निकासी और चेंजिंग रूम पर विशेष ध्यान**

बरसात को देखते हुए उपजिलाधिकारी ने मेले परिसर में जल निकासी के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा, ताकि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या न हो। अभरण सरोवर में लगाई गई सुरक्षा जालियों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने महिलाओं की सुविधा हेतु चेंजिंग रूम बनाए जाने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।

स्वच्छता, बिजली और पानी की व्यवस्था पर जोर

निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी ने विद्युत आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेला स्थल पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए और सभी विभाग समन्वय से कार्य करें।

# लोधेश्वर महादेवा के सड़क मार्ग के निर्माण में अनदेखी

**स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो**

बाराबंकी। लोधेश्वर महादेवा में सड़क मार्ग चौड़ीकरण के तहत सूरतगंज महादेवा मार्ग के दोनों तरफ लगाई गई मानक विहीन इंटरलॉकिंग पहली ही बरसात में बह जाने की खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर संज्ञान में लेते हुए विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर ठेकेदार द्वारा मरम्मत कराई इंटरलॉकिंग मार्ग आज मामूली बरसात होने पर भी पुनः मिट्टी बह जाने के चलते इंटरलॉकिंग धस गई व नीचे से खोखली हो गई। जिसके चलते जिम्मेदार लोक निर्माण विभाग की किरकिरी हो रही है। ज्ञात हो कि 11 जुलाई से श्रावण मास का मेला प्रारंभ हो रहा है जिसमें लाखों लाख की संख्या में दूर दराज से श्रद्धालुओं का आना होगा छोटे बड़े वाहन रोड मार्ग के किनारे ठहराव होता है। इंटरलॉकिंग धस जाने के चलते यदि समय रहते इसको दुरुस्त न कराया गया तो बड़ी दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

# गुरुपूर्णिमा पर आध्यात्मिक आस्था और श्रद्धा से गूंज उठी रामनगरी

» सरयू स्नान, मंदिरों में महोत्सव, संतों के मुख से गूंजा गुरू तत्व का गौरवगान

**स्वराज इंडिया संवाददाता**

अयोध्या। गुरुपूर्णिमा के पावन अवसर पर अयोध्या धाम भोर से ही भक्तिभाव से सराबोर हो उठा। हजारों श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया और नागेश्वरनाथ महादेव का जलाभिषेक किया।शहर के प्रमुख मंदिरों रामजन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, मणिराम दास छावनी, श्रीरामवल्लभाकुंज, दशरथ महल, अशर्फी भवन, तुलसीदास जी की छावनी, हनुमत निवास, सियाराम किला, बावन मंदिर, दिगंबर अखाड़ा, उत्तर तोताद्रि मठ, गहोई मंदिर समेत एक हजार से अधिक मंदिरों में महोत्सव की धूम रही।

संत-महंतों और श्रद्धालुओं ने अपने-अपने गुरुओं की पूजा कर गुरुतत्व की महिमा का गुणगान किया।

**गुरु को बताया अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला दीपस्तंभ**

दशरथ महल के महंत विंदुगद्याचार्य महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य ने कहा, गुरु वह सेतु हैं जो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह दिन उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण का है। हनुमत निवास के आचार्य डॉ. मिथिलेश नंदिनी शरण ने कहा, गुरु हमारे अज्ञान और संशयों से बाहर निकालकर हमें आत्मबोध कराते हैं। यही उनका दिव्य कार्य है।रामलला सदन के महंत जगदगुरु रामानुजाचार्य डॉ. राघवाचार्य ने कहा, आषाढ़ पूर्णिमा को वेदव्यास का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने चार वेद, 18 पुराणों का ज्ञान दिया। इसी कारण आज का दिन 'व्यास पूर्णिमा' भी कहलाता है। गुरु का पूजन प्रतिदिन होना चाहिए, पर आज का दिन विशेष रूप से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का दिवस है। गुरुपूर्णिमा के इस पावन पर्व पर रामनगरी अयोध्या एक बार फिर श्रद्धा, आस्था और आत्मिक चेतना का जीवंत केंद्र बन गई।

डॉ मिथलेश नंदनी शरण जी महाराज

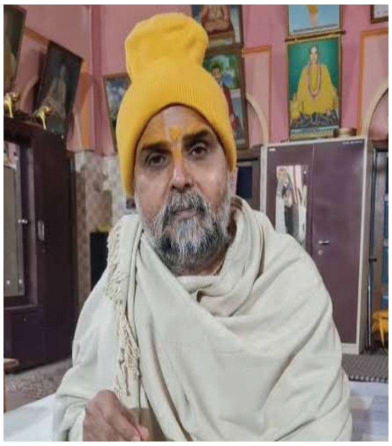
महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य दसरथ महल अयोध्या

# मंत्री नंदी का सीधा वार–कैबिनेट के फैसलों को पलट रही अफसरशाही

## स्मार्टफोन से टैबलेट की ओर 'यू-टर्न' पर भड़के मंत्री नंदी, अफसरशाही की कार्यशैली पर उठाए तीखे सवाल

» मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया

**लखनऊ।** यूपी के केबिनेट मंत्री नंदी ने अपने पत्र में कहा है, अगर मंत्रिपरिषद के निर्णय ही अधिकारियों के विवेक से बदले जा सकते हैं, तो नीति निर्माण का अधिकार किसके पास है? यह प्रणाली लोकतांत्रिक नहीं बल्कि नौकरशाही के नियंत्रण की ओर इशारा करती है।

यह मामला योगी सरकार के भीतर अंदरूनी मतभेद और नौकरशाही बनाम जनप्रतिनिधियों की खींचतान को सतह पर ला रहा है। जहां एक ओर सरकार पारदर्शिता और सुशासन के दावे करती है, वहीं मंत्री के पत्र से यह संकेत मिल रहा है कि अफसरशाही की मनमानी योजनाओं की मंशा को कमजोर कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री इस विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं-अफसरों को जवाबदेह ठहराया जाएगा या मंत्री के सवालों को दरकिनार किया जाएगा।

यह सिर्फ एक पत्र नहीं, सत्ता व्यवस्था में निर्णय के अधिकार को लेकर खड़ा हुआ एक बड़ा सवाल है। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने अफसरशाही के खिलाफ खुला मोर्चा खोलते हुए वित्तीय अनुशासन और

कैबिनेट निर्णयों के पालन को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में नंदी ने आरोप लगाया है कि कैबिनेट में पास हुए स्मार्टफोन वितरण के फैसले को अफसरों ने बदलकर टैबलेट खरीद में तब्दील कर दिया, जिससे न केवल छात्रों के हित प्रभावित हुए बल्कि 3100 करोड़ रुपये का बजट भी लैप्स हो गया।

**कैबिनेट का फैसला, अफसरों की मनमानी :** नंदी ने पत्र में स्पष्ट किया है कि 22 जनवरी 2025 को प्रयागराज कुंभ में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 25 लाख छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। लेकिन मात्र पांच महीने बाद, बिना किसी ठोस कैबिनेट संशोधन के, अफसरों ने स्मार्टफोन की जगह टैबलेट खरीदने का प्रस्ताव पेश कर दिया। जबकि उस समय तक 7.18 लाख टैबलेट और 1.04 लाख स्मार्टफोन वितरण के लिए पहले से स्टॉक में पड़े थे। इसके बावजूद विभाग ने नया प्रस्ताव आगे बढ़ाया, जिससे न केवल प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं बल्कि नीति की पारदर्शिता भी संदिग्ध हो जाती है।

**मांग बनाम आपूर्ति का असंतुलन :** मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में स्मार्टफोन की मांग 27 लाख से अधिक है, जबकि टैबलेट की जरूरत महज 7 लाख छात्रों के लिए है। ऐसे में टैबलेट को प्राथमिकता देना नीतिगत उद्देश्य के प्रतिकूल है और छात्रों को तकनीकी सुविधा देने के नाम पर गैरजरूरी खरीददारी का मार्ग प्रशस्त करता है।

**3100 करोड़ रुपये का बजट हो गया लैप्स :** नंदी के अनुसार इस गैर-जवाबदेह निर्णय प्रक्रिया की वजह से वित्त वर्ष के अंत तक 3100 करोड़ रुपये का बजट लैप्स हो गया, जिससे न केवल छात्रों को नुकसान हुआ बल्कि सरकार की छवि और विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगा है।

### एफडीआई सब्सिडी, लीडा मास्टरप्लान में भी सवाल

मंत्री नंदी ने पत्र में केवल स्मार्टफोन-टैबलेट विवाद ही नहीं उठाया, बल्कि लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (लीडा) के मास्टरप्लान में अचानक बदलाव और एक निजी कंपनी को एफडीआई नीति के तहत मिली सब्सिडी पर भी गंभीर आपत्तियां दर्ज की हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि किस प्रक्रिया और आधार पर इन्हें स्वीकृति मिली, और क्या सभी निर्णयों को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हुई है?

### विभाग का बचाव - सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड

वहीं संबंधित विभाग का कहना है कि सभी बदलाव प्रक्रियागत और शीर्ष स्तर की अनुशंसा के बाद ही किए गए हैं। विभाग का दावा है कि प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए भेजे गए हैं और बिना अंतिम स्वीकृति के कोई नीतिगत परिवर्तन लागू नहीं किया गया है।

---

**नदी में फेंककर की थी हत्या**

## तीन बच्चों की हत्यारी मां को फांसी की सजा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**औरैया।** उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की कोर्ट में एक हत्यारी मां को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल हत्यारी मां ने अपने तीन मासूम बच्चों को नदी में फेंककर उनकी हत्या कर दी थी। कोर्ट ने इस अपराध को दुर्लभ मानते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि हत्यारी मां तालेपुर में सेंगुर नदी में फेंककर अपने तीन मासूम बच्चों की हत्या कर दी। इस मामले की सुनवाई एडीजी-3 न्यायाधीश सैफअहमद की कोर्ट में हुई, जिसके बाद उसे फांसी की सजा दी गई है।

---

**अटकलों का दौर** — **क्या महाराष्ट्र का सियासी गणित कुछ बदलेगा या पहले जैसा रहेगा**

# महाराष्ट्र में क्या होगा महा विकास अघाड़ी का भविष्य

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

**महाराष्ट्र।** जिस तरह पिछले दिनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं और राजनीतिक फिजाओं में दोनों के एक साथ आने को लेकर अटकलों के बवंडर से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल का दौर शुरू होते नजर आ रहा है। भाषावाद के साथ क्षेत्रवाद की टिपिकल ठाकरे राजनीति की ओर शिवसेना उद्धव के बढ़ते कदम और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कदमताल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। इसका पहला संकेत कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान

की तरफसे सामने आ गया है।

राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि हम पहले भी अकेले चुनाव लड़ चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे एक साथ आ चुके हैं। दोनों भाईयों के साथ आने के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या महाराष्ट्र का सियासी गणित कुछ बदलेगा या वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। महाराष्ट्र में जल्द ही नगर निकाय के चुनाव होने हैं। इसमें भारत की सबसे बड़ी नगर निकाय यानी बीएमसी के भी चुनाव होंगे। इस चुनाव को लेकर प्रदेश के दोनों गठबंधनों में कुछ नया समीकरण बनता दिख रहा है। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, कांग्रेस पार्टी का रुख यह है कि हमारा गठबंधन हमारे इंडिया गठबंधन के सहयोगियों-शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) के साथ है। अगर वे किसी अन्य पार्टी, समान विचारधारा वाली पार्टी के साथ अपना गठबंधन करना चाहते हैं, तो यह उनका मामला है।